



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11012020-215327
CG-DL-W-11012020-215327

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 11—जनवरी 17, 2020 (पौष 21, 1941)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11—JANUARY 17, 2020 (PAUSA 21, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... 5

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 21

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 1

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 93

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 15

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 21

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 45

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	5	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	21	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	93	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	15
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	21
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	45
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-01, दिनांक 16 दिसम्बर 2019

सं. एफ. 9-25/2000-यू.3 (ए) पार्ट.3—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 13 जनवरी 2003 की अधिसूचना सं. 9-25/2000-यू.3 के माध्यम से 'अमिता विश्व विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु जिसमें निम्नलिखित पांच शिक्षण संस्थान शामिल हैं, को पांच वर्षों के पश्चात समीक्षा के अध्यधीन, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय घोषित किया था।

- i. अमिता प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, एट्टीमादाई परिसर, कोयम्बटूर;
- ii. अमिता प्रबंधन संस्थान, एट्टीमादाई परिसर, कोयम्बटूर;
- iii. अमिता चिकित्सा विज्ञान संस्थान और अनुसंधान केन्द्र, कोचि;
- iv. अमिता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स साइंस, कोचि; और
- v. अमिता इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, कोचि

3. और जबकि, मंत्रालय की दिनांक 13.01.2003 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार अमिता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु यूजीसी द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने, यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 30 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. 9-25/2000-यू.3ए के माध्यम से अमिता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को अगले पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 13.01.2008 से 12.01.2013 तक बढ़ा दिया था।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 27 मार्च 2017, 19 जनवरी, 2018 और 6 जून, 2018 की अधिसूचना सं. 9-25/2000-यू.3 (ए) पार्ट.3 के माध्यम से 'अमिता विश्व विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु के सम विश्वविद्यालय के दर्जे का 13.01.2013 से 12.07.2019 तक विस्तार इस शर्त के अध्यधीन किया कि आगे विस्तार तभी किया जाएगा यदि सम विश्वविद्यालय के नाम पर एक पृथक सोसायटी का निर्माण किया जाए और सभी चल और अचल परिसंपत्तियों को विधिक रूप से नई बनायी गई सोसायटी के नाम अंतरित किया जाए।

5. और जबकि, यूजीसी ने अमिता विश्व विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कार्य निष्पादन और शैक्षिक परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने संस्थान के शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के आधार पर अमिता विश्व विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु को बहुत उत्कृष्ट ग्रेड प्रदान किया था और सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की

सिफारिश की थी। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर आयोग की दिनांक 16.10.2019 को हुई 544वीं बैठक (मद सं.2.12) में विचार किया गया था जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:

“आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उन संस्थाओं जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा एवं अच्छा” रेटिंग प्रदान की गई है, का समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने/बढ़ाने का निर्णय किया है। तथापि, वे समविश्वविद्यालय जिन्हें शैक्षणिक कार्यनिष्पादन हेतु खराब और औसत रेटिंग प्रदान की गई है, उन्हें विस्तार/निरंतरता प्रदान नहीं की जाएगी।”

6. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श और साथ ही पूर्व की अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुपालन की सुनिश्चितता के पश्चात एतद्वारा अमिता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, तमिलनाडु के समविश्वविद्यालय के दर्जे का 13.07.2019 से आगे विस्तार करती है।

7. अमिता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

सं. एफ. 9-27/2000-यू.3—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्थास को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 1 नवंबर 2004 की अधिसूचना सं. 9-27/2000-यू.3 के माध्यम से जे पी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी) नोएडा, (उत्तर प्रदेश) को तीन वर्षों की समीक्षा के अध्यक्षीन, यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत दे-नोवो श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय घोषित किया था। तत्पश्चात सम-विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा यूजीसी द्वारा की गयी थी। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर 1 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 9-27/2000-यू.3 के अनुसार जे पी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी) नोएडा, (उत्तर प्रदेश) के सम विश्वविद्यालय का दर्जा पांच वर्षों के आगे की अवधि अर्थात् 01.11.2007 से 31.10.2012 के लिए बढ़ा दिया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी), नोएडा (उत्तर प्रदेश) के निष्पादन और शैक्षणिक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी), नोएडा (उत्तर प्रदेश) को शैक्षणिक प्रदर्शन में अच्छी रेटिंग दी थी और विश्वविद्यालय के समवत दर्जे को बनाए रखने की सिफारिश की थी। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर 16.10.2019 को आयोजित आयोग की 544वीं बैठक (मद सं. 2.12) में विचार किया गया जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए:

“आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और उन संस्थाओं जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा एवं अच्छा” रेटिंग प्रदान की गई है, का समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने/बढ़ाने का निर्णय किया है। तथापि, वे समविश्वविद्यालय जिन्हें शैक्षणिक कार्यनिष्पादन हेतु खराब और औसत रेटिंग प्रदान की गई है, उन्हें विस्तार/निरंतरता प्रदान नहीं की जाएगी।”

4. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श के पश्चात जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी), नोएडा (उत्तर प्रदेश) के समविश्वविद्यालय के दर्जे का 01.01.2012 से आगे विस्तार करती है।

5. जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी), नोएडा (उत्तर प्रदेश) द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

सं. एफ. 9-1/2002-यू.3 (पार्ट.1)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्थान को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 21.01.2003 की अधिसूचना सं. 9-1/2002-यू.3 के माध्यम से डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, जिसमें (i) थाई मूंगमबिगाई डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चेन्नई और (ii) डॉ. एम.जी.आर. इंजीनियरिंग कॉलेज, मदुरावायल, चेन्नई शामिल है, को तीन वर्षों की समीक्षा के अधीन, और इस शर्त के अधीन कि यूजीसी एवं एआईसीटीई द्वारा समय-समय पर जारी सम विश्वविद्यालय पर यथा लागू दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन करेगा, सम विश्वविद्यालय घोषित किया था।

3. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 25 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 10-9/2007-यू.3 (ए) के माध्यम से एसीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चेन्नई के एक घटक संस्थान के रूप में डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी थी।

4. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 2 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 9-1/2002-यू.3(पार्ट.1) के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई का सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिनांक 30.06.2019 तक बढ़ा दिया था:

i विनियमों के अनुसार सम विश्वविद्यालय की समग्र भूमि को कम से कम 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टेदारी के माध्यम से अधिग्रहित किया जाएगा।

ii संस्थान यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों/कमियों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5. और इसके अतिरिक्त जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 14 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं. 10/4/2018-यू3(ए) के माध्यम से राज राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बंगलुरु, कर्नाटक के एक घटक संस्थान के रूप में डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी थी।

6. और जबकि, यूजीसी ने डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के कार्य निष्पादन और शैक्षिक परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने संस्थान के शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के आधार पर डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु को बहुत अच्छा ग्रेड प्रदान किया था और सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश की थी। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर आयोग की दिनांक 16.10.2019 को हुई 544वीं बैठक (मद सं.2.12) में विचार किया गया था जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:

"आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उन संस्थाओं जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा एवं अच्छा" रेटिंग प्रदान की गई है, का समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने/बढ़ाने का निर्णय किया है। तथापि, वे समविश्वविद्यालय जिन्हें शैक्षणिक कार्यनिष्पादन हेतु खराब और औसत रेटिंग प्रदान की गई है, उन्हें विस्तार/निरंतरता प्रदान नहीं की जाएगी।"

7. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श और साथ ही पूर्व की अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुपालन की सुनिश्चितता के पश्चात एतदद्वारा डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु के समविश्वविद्यालय के दर्जे का 01.07.2019 से आगे विस्तार करती है।

8. डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

सं. एफ. 9-2/2003-यू.3—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 13.06.2007 की अधिसूचना सं.9-2/2003-यू.3 के द्वारा संतोष मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद; और संतोष डेंटल कॉलेज, गाजियाबाद सहित संतोष विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को इसके निष्पादन का मूल्यांकन करने और यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट की गई कमियों की पुष्टीकरण के संबंध में इसके अनुपालन को सत्यापित करने हेतु यूजीसी की विशेषज्ञ समिति द्वारा एक वर्ष पश्चात समीक्षा करने के अध्यक्षीन “सम विश्वविद्यालय” के रूप में घोषित किया था।

3. और जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 03.11.2017 के ओड़ीशा लिफ्ट इरीगेशन लिमिटेड बनाम रबी संकर पेट्रो एवं अन्य द्वारा दायर की गई सिविल अपील संख्या 17869-17870/2017 (एसएलपी(ग) और संख्या 19807-19808/2017 (एसएलपी ग संख्या 35793-96/2012 से उत्पन्न), विजय कुमार और अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य के शीर्षक में अपने निर्णय आदेश में कहा कि यूजीसी, यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और सम विश्वविद्यालयों को ‘विश्वविद्यालय’ शब्द के उपयोग करने से प्रतिबंधित करने हेतु आज से एक माह के भीतर समुचित कदम उठाएगी।

4. और जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और यूजीसी की सलाह पर यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, दिनांक 11 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 9-2/2003-यू3(ए) के माध्यम से “संतोष विश्वविद्यालय” के नाम से ‘विश्वविद्यालय’ शब्द को हटाकर ‘संतोष’ इस शर्त के साथ बदल दिया कि संतोष अपने नाम से पूर्व ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन साथ में कोष्ठक के साथ “सम विश्वविद्यालय” शब्द का उल्लेख कर सकता है।

5. और जबकि, यूजीसी ने संतोष गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के निष्पादन और शैक्षणिक परिणामों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति, ने अपनी रिपोर्ट में, संतोष गाजियाबाद समविश्वविद्यालय को संस्था की शैक्षणिक निष्पादन पर अच्छे ग्रेड प्रदान किया था और उनकी सम विश्वविद्यालय के दर्जे को जारी रखने के लिए सिफारिश की थी। आयोग द्वारा यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर दिनांक 16.10.2019 को हुई इसकी 544वीं बैठक (मद संख्या 2.12) में विचार गया था जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे:

“आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उन संस्थाओं, जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्य निष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा और अच्छा की रेटिंग प्रदान की गई थी, के सम विश्वविद्यालय का दर्जा होने के लिए जारी रखने/बढ़ाने का निर्णय किया था। तथापि, ऐसे सम विश्वविद्यालय जिन्हें शैक्षणिक कार्य निष्पादन हेतु खराब और औसत रेटिंग प्रदान की गई है, उन्हें विस्तार/निरंतरता प्रदान नहीं की जाएगी।”

6. अब इसलिए, केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा यूजीसी की सलाह पर संतोष, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का सम विश्वविद्यालय दर्जे को दिनांक 13.06.2018 से आगे विस्तार करती है।

5. संतोष, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों की पूर्व अधिसूचना में अनुपालन किया जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

सं. एफ. 9-14/2004-यू.3—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 04 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 9-14/2004-यू.3 के माध्यम से, पोन्नैयाह रामजायम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआरईएसटी) तंजावुर, तमिलनाडु को पांच वर्ष की अनंतिम अवधि के लिए सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने पोन्नैयाह रामजायम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआरईएसटी) तंजावुर, तमिलनाडु के कार्यनिष्पादन और शैक्षिक परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने संस्थान के शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के आधार पर पोन्नैयाह रामजायम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआरईएसटी) तंजावुर, तमिलनाडु को औसत ग्रेड

प्रदान किया था और सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश की थी। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर आयोग की दिनांक 16.10.2019 को हुई 544वीं बैठक (मद सं.2.12) में विचार किया गया था जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:

“आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और उन संस्थाओं जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा एवं अच्छा” रेटिंग प्रदान की गई है, का समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने/बढ़ाने का निर्णय किया है। तथापि, वे समविश्वविद्यालय जिन्हें शैक्षणिक कार्यनिष्पादन हेतु खराब और औसत रेटिंग प्रदान की गई है, उन्हें विस्तार/निरंतरता प्रदान नहीं की जाएगी।”

4. इसके अतिरिक्त, यूजीसी की सिफारिश पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था। अब केंद्र सरकार एतद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पोन्नैयाह रामजायम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआरईएसटी) तंजावुर, तमिलनाडु के सम-विश्वविद्यालय की स्थिति को, इस शर्त पर कि अगले शैक्षिक सत्र अर्थात् 2020-21 में छात्रों के प्रवेश से पूर्व शैक्षिक अधिगम और क्षमता, मानदंडों पर सम-विश्वविद्यालय का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा, 04.01.2013 से 30.06.2020 तक बढ़ाती है। सम-विश्वविद्यालय में पहले से प्रवेश प्राप्त छात्र को पोन्नैयाह रामजायम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआरईएसटी) तंजावुर, तमिलनाडु से उनकी डिग्री प्राप्त होती रहेगी।

5. पोन्नैयाह रामजायम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआरईएसटी) तंजावुर, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

सं. एफ. 9-37/2004-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 08.11.2006 की अधिसूचना सं.9-37/2004-यू.3 के द्वारा शोभित इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, उत्तर प्रदेश को नई दिल्ली के तहत पांच वर्ष की अंतरिम अवधि के लिए नई श्रेणी के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने शोभित इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणामों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में संस्थान के शैक्षणिक प्रदर्शन पर शोभित इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, उत्तर प्रदेश को औसत ग्रेड प्रदान किया और उनके दर्जे को संबद्ध विश्वविद्यालय को बनाए रखने की संस्तुति की। आयोग द्वारा 16.10.2019 को आयोजित 544वीं बैठक (मद संख्या 2.12) में यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:

“आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उन संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय के दर्जे को संबद्ध विश्वविद्यालय बनाए रखने/विस्तारित करने का संकल्प लिया जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा और अच्छा निर्धारित किया गया था। हालांकि, जिन संबद्ध विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए खराब और औसत निर्धारित किया गया था, उन्हें जारी नहीं रखा जाएगा/विस्तरण नहीं दिया जाएगा।”

4. इसके अतिरिक्त, यूजीसी की संस्तुति पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था। अब, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा इसके अध्यक्षीन कि अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2020-21 में छात्रों के दाखिले से पूर्व शैक्षणिक परिणामों और कार्य-निष्पादन मापदंडों के संबंध में समविश्वविद्यालय का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा, दिनांक 08.11.2011 से 30.06.2020 तक समविश्वविद्यालय का दर्जा बढ़ाती है। हालांकि, समविश्वविद्यालय में पहले से ही दाखिल छात्र अपनी डिग्रियां शोभित इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (समविश्वविद्यालय), मेरठ, उत्तर प्रदेश से ही लेते रहेंगे।

5. शोभित इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) के साथ-साथ यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों में समय-समय पर जारी उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करता रहेगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

सं. एफ. 9-46/2004-यू.3—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 17 जनवरी, 2007 की अधिसूचना सं. 9-46/2004-यू.3 के माध्यम से निम्नलिखित चार संस्थानों सहित सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा (गुजरात) को समविश्वविद्यालय घोषित किया था जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत पांच वर्षों की समीक्षा के अध्वधीन होगा:

- i. के. एम. शाह डेंटल कॉलेज और हास्पिटल, ग्राम पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा (गुजरात)
- ii. के.जे. पाण्ड्या कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, ग्राम पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा (गुजरात)
- iii. एस.बी.के.एस. चिकित्सा संस्थान और अनुसंधान केन्द्र, ग्राम पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा (गुजरात)
- iv. सुमनदीप नर्सिंग कॉलेज, ग्राम पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा (गुजरात)

3. और जबकि, यूजीसी ने सुमनदीप विद्यापीठ, वडोदरा (गुजरात) के निष्पादन और शैक्षणिक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुमनदीप विद्यापीठ, वडोदरा (गुजरात) को शैक्षणिक प्रदर्शन में बहुत अच्छी रेटिंग दी थी और विश्वविद्यालय के समवत दर्जे को बनाए रखने की अनुशंसा की थी। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर 16.10.2019 को आयोजित आयोग की 544वीं बैठक (मद संख्या 2.12) में विचार किया गया जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए:

"आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और उन संस्थाओं जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा एवं अच्छा" रेटिंग प्रदान की गई है, का समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने/बढ़ाने का निर्णय किया है। तथापि, वे समविश्वविद्यालय जिन्हें शैक्षणिक कार्यनिष्पादन हेतु खराब और औसत रेटिंग प्रदान की गई है, उन्हें विस्तार/निरंतरता प्रदान नहीं की जाएगी।"

4. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श के पश्चात सुमनदीप विद्यापीठ, वडोदरा (गुजरात) के समविश्वविद्यालय के दर्जे का 17.01.2012 से आगे विस्तार करती है।

5. सुमनदीप विद्यापीठ, वडोदरा (गुजरात) द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

सं. एफ. 9-51/2004-यू.3—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 08.12.2008 की अधिसूचना सं. 9-51/2004-यू.3 के माध्यम से नुरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन कुमारकोइल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु को पांच वर्ष की अनंतिम अवधि के लिए सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया गया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने नुरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन कुमारकोइल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कार्यनिष्पादन और शैक्षिक परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने संस्थान के शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के आधार पर नुरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन कुमारकोइल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु को औसत ग्रेड प्रदान किया था और सम

विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश की थी। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर आयोग की दिनांक 16.10.2019 को हुई 544वीं बैठक (मद सं.2.12) में विचार किया गया था जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:

“आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और उन संस्थाओं जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा एवं अच्छा” रेटिंग प्रदान की गई है, का समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने/बढ़ाने का निर्णय किया है। तथापि, वे समविश्वविद्यालय जिन्हें शैक्षणिक कार्यनिष्पादन हेतु खराब और औसत रेटिंग प्रदान की गई है, उन्हें विस्तार/निरंतरता प्रदान नहीं की जाएगी।”

4. इसके अतिरिक्त, यूजीसी की सिफारिश पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था। अब केंद्र सरकार एतद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नुरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन कुमारकोइल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु के सम-विश्वविद्यालय की स्थिति को, इस शर्त पर कि अगले शैक्षिक सत्र अर्थात् 2020-21 में छात्रों के प्रवेश से पूर्व शैक्षिक अधिगम और क्षमता, मानदंडों पर सम-विश्वविद्यालय का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा, 08.12.2013 से 30.06.2020 तक बढ़ाती है। सम-विश्वविद्यालय में पहले से प्रवेश प्राप्त छात्रों को नुरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन कुमारकोइल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु से उनकी डिग्री प्राप्त होती रहेगी।

5. नुरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन कुमारकोइल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

सं. एफ.9-23/2005-यू.3—जबकि, केंद्रीय सरकार को यूजीसी की सलाह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 05.01.2009 की अधिसूचना सं. 9-23/2005-यू.3 के तहत लिंगाया प्रबंध और प्रयोगिकी संस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए ‘लिंगाया विश्वविद्यालय’ के नाम और शैली में ‘समविश्वविद्यालय’ घोषित किया था।

3. और जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक की सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया है कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए समुचित उपाय करेगा।

4. और जबकि, केन्द्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार और यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर इस शर्त पर कि ‘लिंगाया विश्वविद्यालय’, फरीदाबाद, हरियाणा अपने नाम के बाद ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का प्रयोग नहीं करेगा किंतु कोष्ठक में ‘समवत विश्वविद्यालय’ शब्द का प्रयोग करने के जरिए ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का विलोपन करके ‘लिंगाया विश्वविद्यालय’ का नाम बदलकर ‘लिंगाया विश्वविद्यालय’ कर दिया गया।

5. और जबकि, यूजीसी ने लिंगाया विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा के कार्य-निष्पादन और शैक्षणिक परिणामों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिंगाया विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा को संस्थान के कार्य-निष्पादन पर अच्छा ग्रेड प्रदान किया है, और इसके समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को जारी रखने की संस्तुति की है। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर दिनांक 16.10.2019 को आयोजित अपनी 544वीं बैठक में विचार किया गया जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया था:

“समिति ने यूजीसी विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उन संस्थाओं के लिए समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को जारी रखने/उसका विस्तार करने का संकल्प किया, जिनका रैंक विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्य-निष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा और अच्छा निर्धारित किया गया था। तथापि, उन समवत विश्वविद्यालय का दर्जा जारी नहीं रखा जाएगा/उसका विस्तार नहीं किया जाएगा, जिनका रैंक शैक्षणिक कार्य-निष्पादन के लिए खराब और औसत था।”

6. अब, इसलिए, यूजीसी की संस्तुति पर, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा दिनांक 05.01.2014 से लिंगाया विद्यापीठ, फरीदाबाद, हरियाणा का समवत विश्वविद्यालय का दर्जा आगे बढ़ाती है।

7. लिंगाया विद्यापीठ, फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) के साथ-साथ यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/ विनियमों में समय-समय पर जारी उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन करता रहेगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

सं. एफ.9-42/2005-यू.3 (ए)—जबकि, केंद्रीय सरकार को यूजीसी की सलाह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 27.06.2008 की अधिसूचना सं. 9-42/2005-यू.3 (ए) के तहत “नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय”, इलाहाबाद, जिसमें राजीव गांधी स्नातकोत्तर कॉलेज शामिल है, को तीन वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए “समविश्वविद्यालय” घोषित किया था।

3. और जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिंशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया है कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

4. और जबकि, केन्द्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार और यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर इस शर्त पर कि “नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय”, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश अपने नाम के बाद “विश्वविद्यालय” शब्द का प्रयोग नहीं करेगा किंतु कोष्ठक में “समवत विश्वविद्यालय” शब्द का प्रयोग कर सकता है, दिनांक 11.01.2018 की अधिसूचना सं. 9-42/2005-यू.3 (ए) के जरिए “विश्वविद्यालय” शब्द का विलोपन कर “नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय” का नाम बदलकर “नेहरू ग्राम भारती” कर दिया गया।

5. और जबकि, यूजीसी ने नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का कार्य-निष्पादन और शैक्षणिक परिणामों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को संस्थान के कार्य-निष्पादन पर खराब ग्रेड प्रदान किया है, और इसके समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को जारी रखने की संस्तुति नहीं की है। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर दिनांक 16.10.2019 को आयोजित अपनी 544वीं बैठक में विचार किया गया जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया था:

‘समिति ने यूजीसी विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उन संस्थाओं के लिए समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को जारी रखने/उसका विस्तार करने का संकल्प किया विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्य-निष्पादन के लिए जिनका रैंक उत्कृष्ट, बहुत अच्छा और अच्छा निर्धारित किया गया था। तथापि, उन समवत विश्वविद्यालय का दर्जा जारी नहीं रखा जाएगा/उसका विस्तार नहीं किया जाएगा, शैक्षणिक कार्य-निष्पादन के लिए जिनका रैंक खराब और औसत था।’

6. इसके अतिरिक्त, यूजीसी की संस्तुति पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था। अब, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा इसके अध्यक्षीन कि अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2020-21 में छात्रों के दाखिले से पूर्व शैक्षणिक परिणामों और कार्य-निष्पादन मापदंडों के संबंध में समवत विश्वविद्यालय का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का समविश्वविद्यालय दर्जा 27.06.2011 से 30.06.2020 तक आगे बढ़ाती है। हालांकि, समवत विश्वविद्यालय में पहले से ही दाखिल छात्र अपनी डिग्रियां नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से ही लेते रहेंगे।

7. नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) के साथ-साथ यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/ विनियमों में समय-समय पर जारी उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन करता रहेगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 16th December 2019

No. F.9-25/2000-U3(A)Pt.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-25/2000-U.3 dated 13th January, 2003, on the advice of UGC, had declared 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil Nadu consisting of following five Institutions as an Institution Deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956 subject to a review after five years:

- i. Amrita Institute of Technology and Science, Ettimadai Campus, Coimbatore;
- ii. Amrita Institute of Management, Ettimadai Campus, Coimbatore;
- iii. Amrita Institute of Medical Sciences and Research Centre, Kochi;
- iv. Amrita Institute of Pharmaceutical Sciences, Kochi; and
- v. Amrita Institute of Nursing Sciences, Kochi.

3. And whereas, as per the provisions of the Ministry's Notification dated 13.01.2003, an Expert Committee was constituted by the UGC to review the functioning of the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore. Further, the Central Government, vide its Notification No.9-25/2000-U.3A dated 30th September, 2016, on the advice of the UGC, extended the status of Deemed to be University of 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil Nadu for another period of five years i.e. from 13.01.2008 to 12.01.2013.

4. And further whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification Nos.9-25/2000-U3(A)Pt.3 dated 27th March, 2017, 19th January, 2018 & 6th June, 2018, on the advice of the UGC, extended the status of Deemed to be University of 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil Nadu from 13.01.2013 to 12.07.2019 subject to condition that further extension shall only be given if a separate Society in the name of Deemed to be University is created and all the moveable and immovable assets are legally transferred in the newly created Society.

5. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu. The Committee, in its report, gave the excellent grade to Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC and also after ensuring compliance of the conditions of the earlier Notifications, hereby extends the Deemed to be University status of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu from 13.07.2019 onwards.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO
Senior Economic Advisor

No. F.9-27/2000-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-27/2000-U.3 dated 1st November, 2004, on the advice of UGC, had declared Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) as an Institution Deemed to be University under De-Novo Category under Section 3 of the UGC Act, 1956 subject to a review after three years. The functioning of the Deemed to be University was subsequently reviewed by the UGC. Further, on the advice of UGC, the Central Government, vide its Notification No.9-

27/2000-U.3 dated 1st October, 2008, extended the Deemed to be University status of Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) for another period of five years i.e. from 01.11.2007 to 31.10.2012.

3. And further whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh). The Committee, in its report, gave the good grade to Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension.”

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) from 01.11.2012 onwards.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh).

V.L.V.S.S. SUBBA RAO
Senior Economic Advisor

No. F.9-1/2002-U.3(Pt.1)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-1/2002-U.3 dated 21.01.2003, on the advice of UGC, had declared Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, comprising (i) Thai Moogambigai Dental College and Hospital, Chennai and (ii) Dr. M.G.R. Engineering College, Maduravoyal, Chennai, as an Institution deemed to be University, subject to review of three years, and also with the condition that it will adhere to the guidelines / instructions issued by UGC & AICTE, from time to time as applicable to the deemed to be university.

3. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.10-9/2007-U3(A) dated 25th September, 2014 permitted inclusion of ACS Medical College & Hospital, Chennai under ambit of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai as a Constituent Institution.

4. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-1/2002-U.3(Pt.1) dated 2nd July, 2018, extended the deemed to be University status to Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai upto 30.06.2019 with the following conditions:

- i. The entire land of the deemed to be university shall be acquired through leasehold up to the minimum period of 30 years as per the Regulations.
- ii. The Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

5. And further whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.10/4/2018-U3(A) dated 14th February, 2019 permitted inclusion of Raja Rajeswari Medical College & Hospital, Bengaluru, Karnataka under ambit of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute (Deemed to be University), Chennai as a Constituent Institution.

6. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai. The Committee, in its report, gave the very good grade to Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, Tamil Nadu on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension.”

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC and also after ensuring compliance of the conditions of the earlier Notifications, hereby extends the Deemed to be University status of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, Tamil Nadu from 01.07.2019 onwards.

8. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, Tamil Nadu.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO
Senior Economic Advisor

No. F.9-2/2003-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-2/2003-U.3 dated 13.06.2007, on the advice of UGC, had declared Santosh University, Ghaziabad, Uttar Pradesh consisting of Santosh Medical College, Ghaziabad; and Santosh Dental College, Ghaziabad as “deemed to be University”, subject to review after one year by an Expert Committee of the UGC to assess its performance and also to verify its compliance with respect to rectification of the deficiencies pointed out in the reports of the UGC’s Expert Committees that visited and physically inspected them.

3. And whereas, the Hon’ble Supreme Court of India, vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 [arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012] filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 [arising out of SLP (C) Nos.35793-96/2012] titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors, held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

4. And whereas, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of “Santosh University” to “Santosh” by deleting the word ‘University’ from its name vide Notification No.9-2/2003-U3(A) dated 11th January, 2018, with the condition that Santosh shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

5. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh. The Committee, in its report, gave the good grade to Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension.”

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh from 13.06.2008 onwards.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO
Senior Economic Advisor

No. F.9-14/2004-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-14/2004-U.3 dated 4th January, 2008, on the advice of UGC, had declared Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu as an Institution Deemed to be University for a provisional period of five years.

3. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu. The Committee, in its report, gave the average grade to Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension.”

4. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu from 04.01.2013 to 30.06.2020 with the conditions that the Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes & performance parameters before admission of the students in the next Academic Session i.e. 2020-21. The students already admitted in Deemed to be University will continue to get their Degrees from the Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST) (Deemed to be University), Thanjavur, Tamil Nadu.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO
Senior Economic Advisor

No. F.9-37/2004-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-37/2004-U.3(A) dated 8th November, 2006, on the advice of UGC, had declared Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh as an Institution Deemed to be University under De-Novo Category for a provisional period of five years.

3. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh. The Committee, in its report, gave the average grade to Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension.”

4. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh from 08.11.2011 to 30.06.2020 with the conditions that the Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes performance parameters before admission of the students in the next Academic Session i.e. 2020-21. The students already admitted in Deemed to be University will continue to get their Degrees from the Shobhit Institute of Engineering & Technology (Deemed to be University), Meerut, Uttar Pradesh.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO
Senior Economic Advisor

No. F.9-46/2004-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-46/2004-U.3 dated 17th January, 2007, on the advice of UGC, had declared Sumandeep Vidyapeeth, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat) consisting of the following four Institutions as an Institution Deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956 subject to a review after five years:

- i. K. M. Shah Dental College and Hospital, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat),
- ii. K. J. Pandya College of Physiotherapy, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat),
- iii. S.B.K.S. Medical Institute and Research Centre, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat), and
- iv. Sumandeep Nursing College, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat).

3. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat). The Committee, in its report, gave the very good grade to Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat) on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension.”

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat) from 17.01.2012 onwards.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat).

V.L.V.S.S. SUBBA RAO
Senior Economic Advisor

No. F.9-51/2004-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-51/2004-U.3 dated 8th December, 2008, on the advice of UGC, had declared Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu as an Institution Deemed to be University for a provisional period of five years.

3. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu. The Committee, in its report, gave the average grade to Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension.”

4. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu from 08.12.2013 to 30.06.2020 with the conditions that the Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes & performance parameters before admission of the students in the next Academic Session i.e. 2020-21. The students already admitted in Deemed to be University will continue to get their Degrees from the Noorul Islam Centre for Higher Education (Deemed to be University), Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO
Senior Economic Advisor

No. F.9-23/2005-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-23/2005-U.3 dated 05.01.2009, on the advice of UGC, had declared Lingaya's Institute of Management & Technology, Faridabad, Haryana as deemed to be University in the name & style of 'Lingaya's University' for the provisional period of five years.

3. And whereas, the Hon'ble Supreme Court of India, vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos. 19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos. 17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos. 35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors. Vs. Kartar Singh & Ors., held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.

4. And whereas, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of "Lingaya's University", Faridabad, Haryana to "Lingaya's Vidyapeeth" by replacing the word 'University' with 'Vidyapeeth' with the condition that Lingaya's Vidyapeeth shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

5. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Lingaya's Vidyapeeth, Faridabad, Haryana. The Committee, in its report, gave the good grade to Lingaya's Vidyapeeth, Faridabad, Haryana on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No. 2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation/extension."

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Lingaya's Vidyapeeth, Faridabad, Haryana from 05.01.2014 onwards.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Lingaya's Vidyapeeth, Faridabad, Haryana.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO
Senior Economic Advisor

No. F.9-42/2005-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-42/2005-U3(A) dated 27.06.2008, on the advice of UGC, had declared "Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya", Allahabad, Uttar Pradesh consisting of Rajiv Gandhi P.G. College as "deemed to be University" for a provisional period of three years.

3. And whereas, the Hon'ble Supreme Court of India, vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos. 19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd. Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos. 17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos. 35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors. Vs. Kartar Singh & Ors., held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.

4. And whereas, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of "Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya" to "Nehru Gram Bharati" by deleting the word 'Vishwavidyalaya' from its name, vide Notification No. 9-42/2005-U3(A) dated 11th January, 2018, with the condition that Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

5. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh. The Committee, in its report, gave the poor grade to Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh on academic performance of the Institution and did not recommend for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No. 2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation/extension."

6. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh from 27.06.2011 to 30.06.2020 with the conditions that the Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes & performance parameter before admission of the students in the next Academic Session i.e. 2020-21. However, the students already admitted in Deemed to be University will continue to get their Degrees from the Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO
Senior Economic Advisor